

आयकर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़ बनाम ओ. पी. खन्ना
एंड संस (सुरिंदर सिंह, जे।

10. निष्कर्ष के लिए, अधिनियम की धारा 13-ए केवल तलाक के लिए याचिका में वैकल्पिक पट्टेदार को न्यायिक अलगाव की राहत देने के लिए अदालत में विवेकाधिकार प्रदान करती है, बशर्ते कि अधिनियम की धारा 13 द्वारा निर्धारित इसके लिए अपेक्षित आधार स्थापित किया गया हो।

11. अब उपरोक्त नियम को लागू करते हुए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं माना कि प्रतिवादी-पति पूरी तरह से गलती पर था और, जाहिर है, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री का हकदार नहीं था, जिसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी-पति पूरी तरह से दोषी पक्ष है, पत्नी का यह रुख कि उसी के कारण, वह उसके साथ सहवास फिर से शुरू नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से उचित था। अपीलकर्ता-पत्नी के दरवाजे पर दूर-दूर तक कोई वैवाहिक कदाचार नहीं रखा जा सकता था। नतीजतन, उसके खिलाफ कोई राहत नहीं दी जा सकती। इसलिए, अधिनियम की धारा 13-ए को स्थिति की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता था और बड़े सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश ने इसका सहारा लेने में गलती की। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तथ्य के निष्कर्षों ने एक तरह से अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है क्योंकि प्रतिवादी-पति ने इसके खिलाफ कोई अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना था और अन्यथा भी उनके खिलाफ कम से कम सार्थक चुनौती नहीं उठाई जा सकती थी। इसलिए इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को निचली अदालत के फैसले के साथ-साथ खारिज किया जाता है और पति द्वारा पसंद की गई तलाक की याचिका को खारिज कर दिया जाता है; अपीलकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा।

आर. एन. मित्तल और सुरिंदर सिंह से पहले, जेजे. आई. टी. आयुक्त,
हरियाणा और
चंडीगढ़, - आवेदक।
बनाम

ओ. पी. खन्ना एंड संस, - उत्तरदाता।

आयकर संदर्भ सं. 1976 का 146

23 अप्रैल, 1982।

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 32 (1) - एक करदाता द्वारा अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भवन - भवन में स्थापित विद्युत फिटिंग और मशीनरी आदि - व्यवसाय, हालांकि, वास्तव में कुछ समय बाद शुरू हुआ - बिल्डिंग जी और विद्युत फिटिंग के लिए मूल्यहास - क्या इसकी खरीद की तारीख से दवा किया जा सकता है - शब्द का उपयोग? धारा 32 (1) में होता है - इसका अर्थ

माना जाता है कि जब एक नई इकाई स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें "टी कलश कुंजी" के चरण से पहले कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शामिल होती हैं, जैसा कि तकनीकी रूप से कहा जाता है। इकाई की स्थापना की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से उसी के लिए एक उपयुक्त भवन की व्यवस्था के साथ शुरू होगी। इसके बाद यूनिट के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करने के लिए विद्युत या अन्य फिटिंग की स्थापना की जाएगी। मशीनरी की स्थापना अगला कदम होगा और उसके बाद इकाई को चलाने के लिए जन-शक्ति, तकनीकी या गैर-तकनीकी की व्यवस्था करनी होगी। कच्चे माल का प्रावधान इसके बाद आएगा। इसके अलावा, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा और फिर ही इकाई के वास्तविक कामकाज के लिए मंच तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उद्योग की प्रकृति और क्षमता तथा इकाई के पूंजीगत परिव्यय के आधार पर विचार करने योग्य समय लगना अनिवार्य है। प्रस्तावित उद्योग के आवास के लिए एक भवन की व्यवस्था किए जाने और आवश्यक विद्युत फिटिंग किए जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि भवन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के अर्थ के भीतर उपयोग के लिए नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में, करदाता भवन के लिखित मूल्य और उसकी खरीद की तारीख से उसमें विद्युत फिटिंग के संबंध में मूल्यहास का दावा करने का हकदार होगा। (पैरा 6)।

आयकर अपीलीय अधिकरण (चंडीगढ़ पीठ), चंडीगढ़ द्वारा बनाए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के संदर्भ में इस माननीय न्यायालय को उसकी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया गया है। आकलन वर्ष 1971-72 के लिए 1974-75 का 895 और 1976-77 का आर.ए.

पीठ ने कहा, 'क्या मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण का यह कहना सही था कि आकलन वर्ष 1971-72 के लिए करदाता की कारोबारी आय की गणना करते समय चंडीगढ़ की इमारत के संबंध में मूल्यहास की अनुमति दी जानी चाहिए थी?'

अपीलकर्ता की ओर से अशोक भान, वकील।

रोमेश कुमार, एडवोकेट, रस पोप के साथ भागीरथ दास।
निर्णय

सुरिंदर सिंह, जे.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, अमृतसर पीठ (चंडीगढ़ में शिविर) के निर्णय के विरुद्ध राजस्व द्वारा शुरू किए गए इस संदर्भ को ट्रिब्यूनल द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत निम्नलिखित प्रश्न पर राय व्यक्त करने के लिए इस न्यायालय को भेज दिया गया है:

"क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलीय न्यायाधिकरण का यह कहना सही था कि भवन के संबंध में मूल्यहास भत्ता दिया जाना चाहिए था।

आयकर आयुक्त हरियाणा और चंडीगढ़ वी. ओ. पी. खन्ना
और एस. एस. (सुरिंदर सिंह, जे.)

आकलन वर्ष 1971-72 के लिए करदाता की व्यावसायिक आय की गणना करते समय चंडीगढ़?

(2) मामले के बयान में उल्लिखित तथ्य यह है कि प्रतिवादी-निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जो आकलन वर्ष 1971-72 (लेखा वर्ष 1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971) के दौरान जेमिनी प्रिंटर्स, अंबाला कैंट के नाम और शैली के तहत एक प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय कर रहा था। करदाता ने अपनी आय 58,711 रुपये घोषित की है। आयकर अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के समय, करदाता ने चंडीगढ़ में कारखाने की इमारत के लिखित मूल्य और उसमें कुछ विद्युत फिटिंग के संबंध में 10,743 रुपये के मूल्यहास का दावा किया। यह विवादित नहीं है कि 27 नवंबर, 1970 को करदाता द्वारा कारखाने की इमारत का पीछा किया गया था। हालांकि, मूल्यहास के दावे को आयकर अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उक्त इमारत का उपयोग वास्तव में लेखा वर्ष में नहीं किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख

किया गया है। आयकर अधिकारी ने आकलन वर्ष के लिए प्रतिवादी की आय 1,10,060 रुपये बताई।

(3) प्रतिवादी-करदाता ने अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, लेकिन वह उस तिमाही से कोई राहत पाने में विफल रहा। इसके बाद करदाता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया, जिसने उसकी अपील स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि चंडीगढ़ में इमारत को करदाता ने प्रिंटिंग प्रेस के अपने कारोबार को अंबाला से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के लिए खरीदा था और खरीद अपने व्यवसाय के उद्देश्य से की गई थी, इसलिए वह उक्त इमारत और उसमें बिजली के प्रतिष्ठानों के संबंध में मूल्यहास दावे का हकदार था। राजस्व विभाग द्वारा इस न्यायालय को वर्तमान संदर्भ इस प्रकार शुरू किया गया था।

(4) जहां तक तथ्यों का संबंध है, जैसा कि पूरी तरह से देखा गया है, पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी ने 27 नवंबर, 1970 को चंडीगढ़ में नई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने बार में इस बात पर सहमति जताई कि करदाता 30 सितंबर, 1971 को अंबाला से चंडीगढ़ की नई इमारत में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान संदर्भ में विवाद का एकमात्र कारण यह है कि क्या प्रतिवादी को 22 नवंबर, 1970 से 31 मार्च, 1971 की अवधि के लिए भवन और विद्युत फिटिंग के संबंध में मूल्यहास का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् चार महीने से कुछ अधिक समय तक।

(5) पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा संबोधित तर्क आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) में होने वाले 'प्रयुक्त' शब्द की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, एक करदाता अपने स्वामित्व वाली इमारतों, मशीनरी आदि के संबंध में मूल्यहास का दावा कर सकता है और अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। राजस्व विभाग के वकील अशोक भान ने दलील दी है कि 'इस्तेमाल' शब्द 123 बी के वास्तविक उपयोगकर्ता को दर्शाता है और अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने आयकर आयुक्त बनाम आयकर आयुक्त की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करने की मांग की है। जलवाजी राव > शुगर कंपनी लिमिटेड (1)। उक्त प्राधिकरण के संदर्भ से यह पता चलता है कि यह मशीनरी के मामले से संबंधित है न कि भवन से। मशीनरी के उपयोग में एक इमारत से अलग परिस्थितियों का एक सेट शामिल है। इस प्राधिकरण में पुरसा लिमिटेड के परिसमापक बनाम उच्चतम न्यायालय का निर्णय आयकर आयुक्त, बिहार (2) पर ध्यान दिया गया और उक्त प्राधिकरण के संदर्भ से यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने, व्यवसाय के उद्देश्य के लिए मशीनरी या संयंत्र के उपयोग के संबंध में प्रश्न पर निर्णय लेते हुए, 'प्रयुक्त' शब्द की व्याख्या को खुला छोड़ दिया, जहां तक यह सक्रिय या निष्क्रिय उपयोग के बीच के अंतर से संबंधित था। इस अंतर को वास्तव में आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम बॉम्बे में उजागर किया गया है। सिध्नाथ भास्कर साठे, (3) लेकिन फिर उक्त प्राधिकरण फिर से मशीनरी के मामले से संबंधित है, न कि एक इमारत से। किसी भवन के मामले से संबंधित कोई प्रत्यक्ष प्राधिकारी नहीं होने के कारण, इस मामले पर प्रथम सिद्धांतों पर विचार करना होगा।

(6) यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि जब एक नई इकाई स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें "टर्न की" के चरण से पहले कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शामिल होती हैं जैसा कि तकनीकी रूप से कहा जाता है। इकाई की स्थापना की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से उसी के लिए एक उपयुक्त भवन की व्यवस्था के साथ शुरू होगी। इसके बाद यूनिट के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिकल या अन्य फिटिंग की स्थापना की जाएगी। मशीनरी की स्थापना अगला कदम होगा और उसके बाद इकाई को चलाने के लिए मानव शक्ति, तकनीकी या गैर-तकनीकी की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद कच्चे माल का प्रावधान आता है। इसके अलावा, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करना होगा।

और उसके बाद ही मंच पर पहुंचना होगा।

- (1) (1969) 71 आई.टी.आर.
- (2) (1954) 25 आई.टी.आर.
- (3) (1937) 5 आई.टी.आर. 621.

आयकर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़ बनाम ओ.पी. खन्ना
एंड संस (सुरिंदर सिंह, जे.)

इकाई का वास्तविक कार्यकरण। ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया में काफी समय लगना तय है, जो निश्चित रूप से औद्योगिक संस्थान की प्रकृति और क्षमता और इकाई के पूंजीगत परिव्यय पर निर्भर करता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रस्तावित उद्योग के आवास के लिए एक भवन की व्यवस्था किए जाने और आवश्यक विद्युत फिटिंग किए जाने के बाद, क्या यह कहा जा सकता है कि भवन एचका उपयोग नहीं किया गया है? पक्षकारों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि राजस्व के विद्वान वकील की यह दलील कि जब इकाई वास्तव में काम करना शुरू कर देती है, तभी बिल्डिंग जी का उपयोग किया जा सकता है, स्वीकार किया जाता है, तो इससे अतार्किक परिणाम होंगे। आइए हम इसकी क्षमता की जांच करने के लिए विवाद का परीक्षण करें। तर्क के लिए, हम एक ऐसे मामले की कल्पना कर सकते हैं जहां एक उद्यमी इमारत के लिए व्यवस्था करता है, आवश्यक मशीनरी और अन्य फिटिंग के साथ-साथ आवश्यक मशीनरी को भी शामिल करता है, और यहां तक कि इकाई को चलाने के लिए आवश्यक मानव शक्ति को भी शामिल करता है। हालांकि, जब इकाई वास्तविक कामकाज के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, तो आवश्यक कच्चे माल की अचानक अनुपलब्धता होती है या कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप हालांकि उद्यमी ने अपना सारा निवेश व्यवसाय में लगा दिया है, लेकिन उक्त परिस्थिति के कारण, वह इकाई को एक निश्चित अवधि के लिए परिचालन में लाने में सक्षम नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में। ऐसी स्थिति में, क्या यह कहना उचित होगा कि उद्यमी केवल कच्चे माल की नोमापरिवर्तनशीलता या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य परिस्थिति के कारण अपनी इकाई वाले भवन के संबंध में किसी भी मूल्यहास का दावा करने का हकदार है। पूछे गए प्रश्न का हमारा उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक है और इस निष्कर्ष का कारण सरल है। भवन की व्यवस्था करने के बाद, उद्यमी द्वारा भवन को इकाई में चलाने के लिए गियर में सेट करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम, इसे 'उपयोग' करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा।

(7) कानूनी प्रस्ताव पर, प्रतिवादी निर्धारिती के वकील श्री भागीरथ दास ने साराभाई मैनेजमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है। आयकर आयुक्त, गुजरात, (4) जो इस संदर्भ में शामिल बिन्दु के निर्धारण में कुछ सहायता प्रदान करता है। - मामला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संबंधित था, जिसका मुख्य उद्देश्य अचल संपत्ति हासिल करना और इसे देना था,

- (4) (1976) 102 आई.टी.आर.

निवास या व्यवसाय के उद्देश्य से या तो पट्टे पर या लाइसेंस पर, भंडारण, घड़ी और वार्ड सुविधाओं, कैंटीन, जलपान कक्ष आदि सहित सभी सहायक सुविधाओं के साथ। उक्त मामले में, करदाता ने इमारत और उस अवधि से संबंधित अन्य सुविधाओं के संबंध में मूल्यहास का दावा किया था, जिसमें इमारत को पट्टे पर देने की तैयारी चल रही थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा था कि करदाता उक्त अवधि के लिए मूल्यहास का दावा करने का हकदार होगा। वर्तमान मामले के तथ्य हालांकि बिल्कुल समान नहीं हैं, लेकिन

चंडीगढ़ में इमारत की खरीद के बाद प्रतिवादी-करदाता ने इकाई को चलाने के लिए विद्युत फिटिंग स्थापित की थी। जैसा कि पहले ही देखा गया है, प्रतिवादी कुछ महीनों के भीतर उक्त इमारत में अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने में सक्षम था। इस प्रकार यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि इस क्षणभंगुर अवधि के दौरान, निर्धारिती द्वारा खरीदी गई इमारत का "उपयोग" किया गया था।

(8) जैसा कि उपर्युक्त कथन का परिणाम है, इस न्यायालय को दिए गए प्रश्नों का सकारात्मक रूप में अर्थात् प्रतिवादी-निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध उत्तर देना चाहिए। मामले की परिस्थितियों में, इस संदर्भ की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.के.एस.

एस.एस. संधअवालिया से पहले, सी.जे. & डी.एस. तेवतिया, जे।

दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1979 का 921।

27 अप्रैल, 1982।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 301, 304, 305, 366 और 372 - पंजाब आबकारी अधिनियम (1914 का 1) - धारा 31, 32 - पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 1968, 1969 और 1974 - उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जारी राजकोषीय आदेश जो उस समय पहले से मौजूद एक निश्चित दर पर निर्यात शुल्क लगाते हैं। संविधान के लागू होने के बाद - आक्षेपित आदेशों द्वारा संशोधन द्वारा बढ़ाया गया ऐसा कर्तव्य - ऐसे आदेश - चाहे अनुच्छेद 366 के संदर्भ में "मौजूदा कानून" हों ताकि अनुच्छेद 372 द्वारा संरक्षित किया जा सके - बड़े पैमाने पर वृद्धि

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा